लोक सभा सचिवालय

शोध एवं सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लार्डिस 3/2013/ईएफ

अगस्त 2013

अमरीकी डॉलर ($) की तुलना में भारतीय रुपया (₹): वर्तमान परिप्रेक्ष्य

8 जुलाई, 2013 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में 61.05 की रिकार्ड गिरावट आई है। इस समय तीव्र अवमूल्यन के कारण भारतीय रुपये को उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की अल्प निष्पादक मुद्राओं में देखा जा रहा है। भारतीय रुपया बनाम अमेरिकी डॉलर के मूल्य में गिरावट के कारण घरेलू के साथ-साथ वैश्विक दोनों रहे हैं।

रुपये के मूल्य का उद्धरण मांग और आपूर्ति के सरल आर्थिक नियम का अनुसरण करता है। यदि भारत में अमेरिकी डॉलर की इसकी आपूर्ति की अपेक्षा अधिक मांग है तो रुपये की कीमत में गिरावट आएगी और उसमें सुधार भी होगा। यद्यपि अमेरिकी डॉलर की मांग आयातकों द्वारा उत्पन्न की गई है क्योंकि उन्हें अपने आयात के लिए अधिक डॉलरों की जरूरत होती है, फिर भी इसकी आपूर्ति विशेषकर उन विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा घटायी जाती है जो अनेक कारणों से अपनी निवेश राशि वापिस ले लेते हैं और डॉलर भारत से बाहर ले जाते हैं। इसी प्रकार डॉलर की आपूर्ति अपने राजस्व से डॉलर लाने वाले निर्यातकों द्वारा, अधिक धनराशि जमा करने वाले अनिवासी भारतीयों द्वारा और अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भारत में अधिक डॉलर लाने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा स्थापित की जाती है। वर्तमान में मांग और आपूर्ति पक्ष के कुछ घटक अनुकूल रूप से काम नहीं कर रहे हैं जिससे रुपये की कीमत में गिरावट आ रही है। गत 20 वर्षों में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया की विनिमय दर नीचे सारणी में दी गई है:

तालिका-1: रुपया बनाम अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर (वार्षिक औसत)

वर्ष	बाजार विनिमय दर
1994-95	31.39
1995-96	33.44
1996-97	35.49
1997-98	37.16
1998-99	42.07
1999-2000	43.33
2000-01	45.68
2001-02	47.69
2002-03	48.40
2003-04	45.95

वर्ष	बाजार विनिमय दर
2004-05	44.93
2005-06	44.27
2006-07	45.28
2007-08	40.24
2008-09	45.92
2009-10	47.41
2010-11	45.57
2011-12	47.92
2012-13	54.41
2 अगस्त 2013	60.80

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

ग्राफ क: अमरीकी डॉलर में रुपये का परिवर्तन मूल्य–1994-95 से

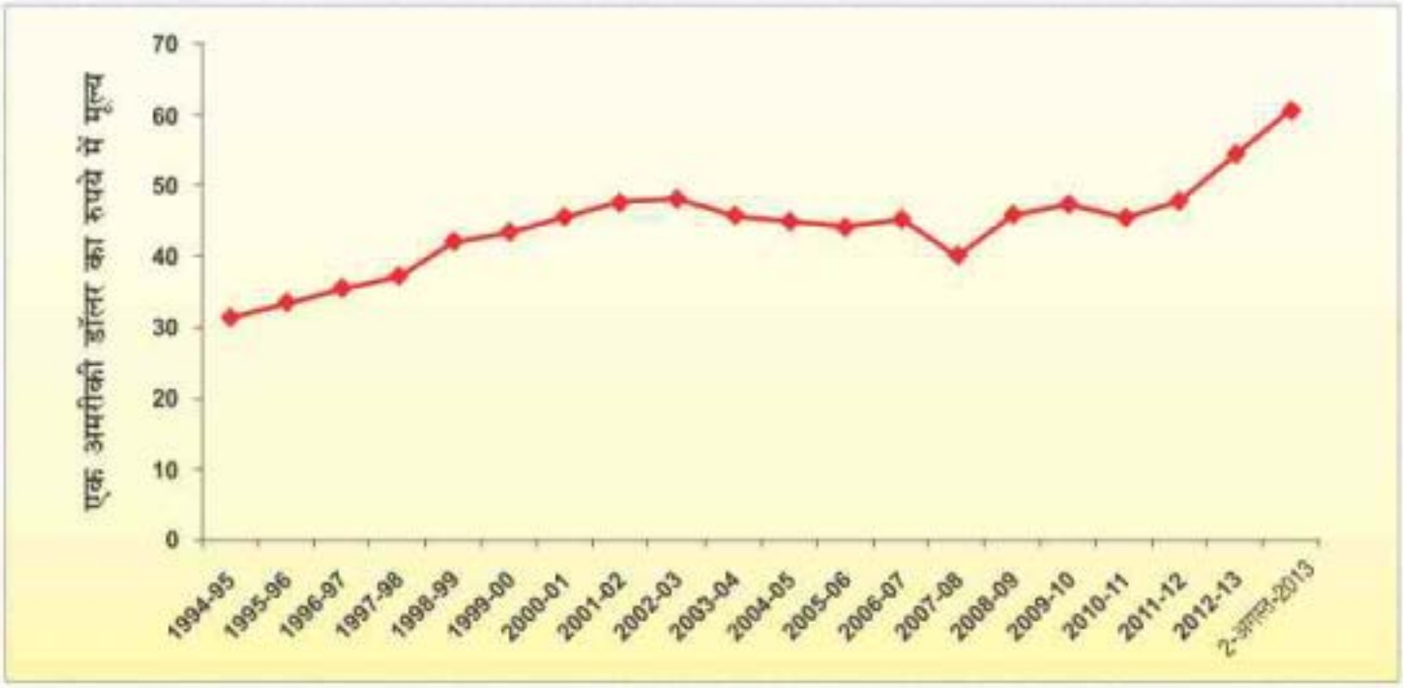

भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं के मूल्य में अवमूल्यन की तुलनात्मक स्थिति सारणी-2 में दी गई है।

तालिका-2: उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं के मूल्य में अवमूल्यन

	(30 मार्च, 2012-29 मार्च, 2013)	(29 मार्च, 2013-2 अगस्त, 2013)
अर्जेन्टीना पेसो	14.5	7.2
ब्राजील का रिआल	8.9	12.1
दक्षिण अफ्रीकी रैन्ड	16.6	7.9
भारतीय रुपया	5.9	10.5
इंडोनेशियाई रुपिया	5.5	5.5
रूसी रूबल	5.6	6.1

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

रुपये के अवमूल्यन के कारण

रुपये के लिए कठिनाइयां पैदा करने वाले कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी

सामान्य शब्दों में, राजकोषीय घाटे का अर्थ है आय की तुलना में व्यय अधिक होना है। वर्तमान में भारत की करों से अर्जित आय की तुलना में व्यय अधिक है, परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है। इन व्ययों का एक प्रमुख हिस्सा अनुदानों में चला जाता है जिससे राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी होती है। बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण विदेशी निवेशकों में कुछ हद तक असुरक्षा का भाव है और वे भारत से अपना धन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इससे रुपये के अवमूल्यन की संभावना और बढ़ती है। तालिका 3 में वर्ष 2003-04 से भारत के राजकोषीय घाटे में आए रुझान दर्शाए गए हैं:–

तालिका-3: वर्ष 2003-04 से राजकोषीय घाटे में आये रुझान [सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का प्रतिशत]

वर्ष	राजकोषीय घाटा
2003-04	4.3
2004-05	3.9
2005-06	4.0
2006-07	3.3
2007-08	2.5
2008-09	6.0
2009-10	6.5
2010-11	4.8
2011-12	5.8
2012-13 (पी)	4.9
2013-14 (बी.ई.)	4.8

पी.: अनंतिम
बी.ई.: बजट अनुमान
स्रोत: वित्त मंत्रालय

ग्राफ ख: वर्ष 2003-04 से भारत के राजकोषीय घाटे का रुझान (स.घ.उ. का प्रतिशत)

चालू खाते में बढ़ता घाटा

तेल जो हमारे आयातों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, की बढ़ती हुई मांग के कारण भारत मूलत: एक आयातक देश बन गया है। चालू खाते में घाटा (सीएडी) तब होने लगता है जब एक देश में वस्तुओं, सेवाओं और अंतरण का कुल आयात निर्यातों से अधिक हो जाता है। हाल में, भारत का सीएडी बहुत अधिक बढ़ा है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार रुपये की कमजोर स्थिति तथा अपेक्षाकृत कम निर्यातों के चलते आने वाले महीनों में हमारा सीएडी वित्तीय वर्ष 2012-13 की अंतिम तिमाही के सीएडी (जो जीडीपी का 3.6 प्रतिशत था) से अधिक हो जाएगा। इतने अधिक सीएडी के कारण भारत जैसा देश विदेशी संस्थागत निवेशकों पर भरोसा करता है ताकि विदेशी पूंजी के प्रयोग से सीएडी के घाटे को पूरा किया जा सके। चूंकि भारत में निवेश करने वाले संस्थागत निवेशक अंतर्राष्ट्रीय बाजार अनिश्चितताओं से सीधे प्रभावित होते हैं, अत: यह काफी जोखिम भरा होता है क्योंकि इस प्रकार की विदेशी पूंजी का आना अचानक ही बंद भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त यूरो जोन जो भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके कारण भारत के निर्यातों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है क्योंकि यूरो जोन से मांग में भारी कमी आई है। चीन को होने वाले निर्यात में भी काफी कमी आई है। परिणामत: भारत के चालू खाते में घाटा लगातार बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहे हैं जिसके कारण रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। तालिका-4(क) और तालिका-4(ख) में भारत के चालू खाते में बढ़ते हुए घाटे के वर्तमान रुझानों को दर्शाया गया है तथा तालिका-5 में वर्ष 2011-12 के दौरान चालू खाते में घाटे की तिमाही स्थिति दर्शाई गयी है।

तालिका-4 (क): चालू खाता जमा (2007-08 से 2012-13)

वर्ष	(बिलियन अमरीकी डॉलर)
2007-08	-15.73
2008-09	-27.91
2009-10	-38.18
2010-11	-48.05
2011-12 (पीआर)	-78.15
2012-13 (पी)	-88.16

पीआर: आंशिक रूप से संशोधित
पी: प्रारंभिक
स्रोत: वित्त मंत्रालय

ग्राफ ग: 2007-08 से चालू खाता जमा (बिलियन अमरीकी डॉलर)

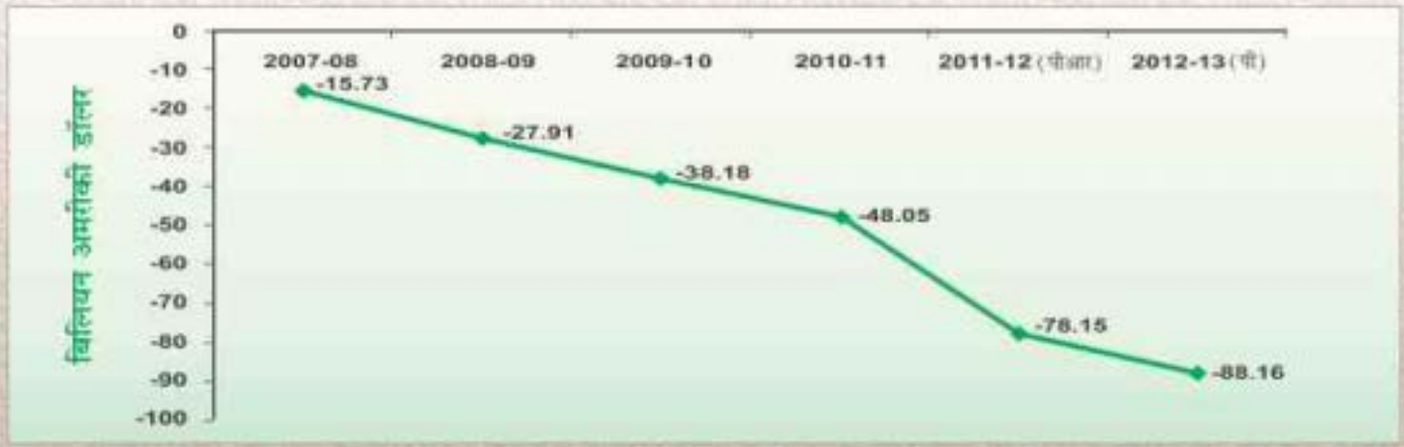

तालिका-4(ख): चालू खाता घाटा (2007-08–2012-13)
(जीडीपी का प्रतिशत)

वर्ष	घाटा
2007-08	1.3
2008-09	2.3
2009-10	2.8
2010-11	2.8
2011-12 (पीआर)	4.2
2012-13 (पी)	4.8

पीआर: आंशिक रूप से संशोधित
पी: प्रारंभिक
स्रोत: वित्त मंत्रालय

ग्राफ घ: 2007-08 से चालू खाता घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)

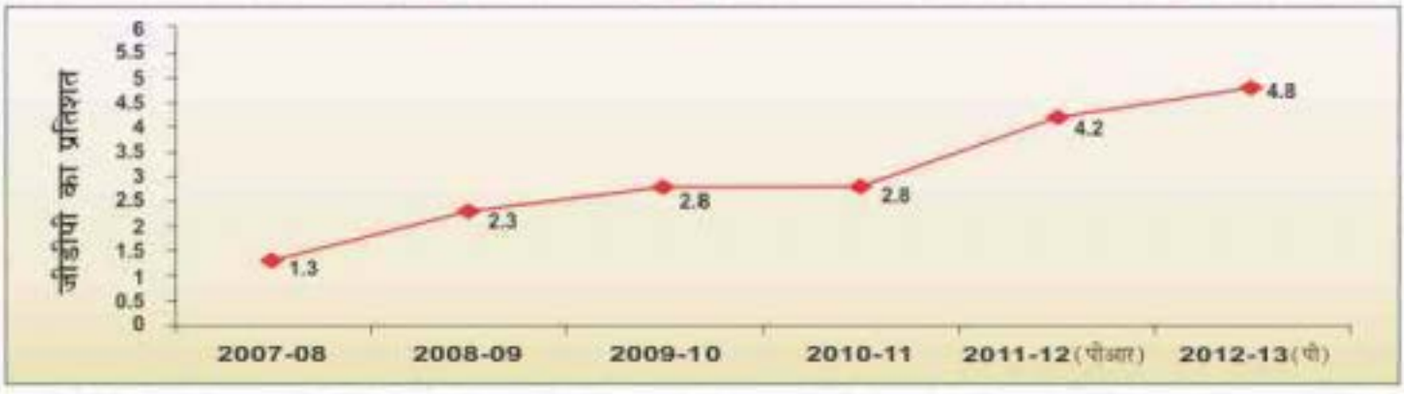

तालिका-5: चालू खाता घाटा (बिलियन अमरीकी डॉलर): 2011-12 और 2012-13 तिमाही

2011-12				2012-13			
क्यू 1	क्यू 2	क्यू 3	क्यू 4	क्यू 1	क्यू 2	क्यू 3	क्यू 4 (पी)
17.4	18.9	20.2	21.7	16.9	21.0	31.9	18.1

पी: प्रारंभिक
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

ग्राफ ङ: वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए चालू खाता घाटा बिलियन अमरीकी डॉलर में (त्रैमासिक)

तेल मूल्य

भारत के कुल आयातों में तेल आयात का हिस्सा सबसे बड़ा है तथा वर्ष प्रति वर्ष इसकी मांग बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का मूल्य यूएस डॉलर में आंका जाता है। अत: भारतीय रुपये को प्रभावित करने वाले घटकों में तेल मूल्य भी एक घटक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों तथा भारत में तेल के आयात की बढ़ती मात्रा से तेल आपूर्तिकर्ता को भुगतान हेतु डॉलर की मांग का दबाव भी बना है। डॉलर की मांग बढ़ने से डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में और कमी आ रही है।

कमजोर पूंजी बाजार

यदि पूंजी बाजार (शेयर बाजार) में उछाल आता है तो भारत में डॉलर का निरंतर आगम बना रहता है जिससे देश में डॉलर की आपूर्ति में वृद्धि होती है। दुर्भाग्यवश, वर्तमान स्थिति बिल्कुल विपरीत है। यद्यपि 2012-13 में कुल एफआईआई प्रवाह 2011-12 की तुलना में अधिक था परन्तु मई 2013 के अंतिम सप्ताह से अमरीकी फेडरल रिजर्व के मुद्रा प्रोत्साहन कार्यक्रम (क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम) से बहिर्गमन पर अग्रिम दिशा-निर्देश का पूंजी बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परिणामस्वरूप डॉलर की आपूर्ति कम होने तथा मांग अधिक होने के कारण डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट आयी है।

अमरीकी अर्थव्यवस्था में सुधार के संबंध में अनुमान तथा फेडरल रिजर्व द्वारा इसके क्वान्टिटेटिव ईजिंग को कम करने की संभावना

मुद्रा मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझानों से भी प्रभावित होती है। मई 2013 से जबकि यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन श्री बेन बर्नांके ने घोषणा की कि यदि अमरीकी अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया जारी रहती है तो फेडरल रिजर्व अपने क्वान्टिटेटिव ईजिंग (क्यूई)* को धीरे-धीरे समाप्त कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। क्यूई कार्यक्रम के हिस्से के रूप में फेडरल रिजर्व बड़ी मात्रा में बांड खरीदता रहा है तथा इस प्रक्रिया में उसने मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया है और ब्याज दरों में भी ऐतिहासिक कमी की है। इन सभी कारणों से अधिकांश विकासशील देशों की मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि हुई है। मुख्य रूप से अमरीकी अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण अमरीकी डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के परिणामस्वरूप और चालू खाता घाटे के उच्च स्तरों के कारण अर्थव्यवस्थाओं (भारत सहित) की मुद्राओं का अवमूल्यन हो रहा है।

अस्थिर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार

विश्व में सभी मुद्राओं के मूल्यों, पूंजी प्रवाह तथा स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव से भी भारतीय रुपये पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा है। कुछ समय से भारतीय रुपये की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव देखा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय विनिमय दर नीति बराबर मूल्य प्रणाली से बदलकर बास्केट पेग आधारित और तत्पश्चात्, प्रबंधित परिवर्तनशील (फ्लोटिंग) विनिमय प्रणाली बन गई है। मार्च, 1993 से लागू परिवर्तनशील व्यवस्था का उद्देश्य विनिमय दर हेतु कोई स्पष्ट या अन्तर्निहित लक्ष्य निर्धारित किए बिना व्यवस्थित बाजार परिस्थितियों के माध्यम से अस्थिरता को नियंत्रित करना रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक न तो विनिमय दर को लक्षित करता है और न ही हस्तक्षेप करने के लिए आंशिक अथवा वास्तविक विनिमय दरों हेतु कोई निश्चित बैंड है। तथापि, अत्यधिक अस्थिर बाजार परिस्थितियों में बाजार को व्यवस्थित बनाए रखने और व्यापक तेजी, जिससे मुद्रा के मूल्य में और तीव्र उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, को रोकने के लिए, स्थिति को सुगम बनाने वाली पहलें की जाती हैं।

पूंजी निर्गम

अन्तर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में अस्थिरता तथा गिरावट के दृष्टिगत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा विभिन्न उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं से अपनी धनराशि निकाल लिए जाने की संभावना होती है। जब अर्थव्यवस्था सुचारु रूप से चल रही हो और उसका शेयर बाजार अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो तो विदेशी निवेशक वहां बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं। यह सर्वविदित है कि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का प्रभुत्व है। अमरीका में बहुत कम ब्याज दरों तथा घरेलू अर्थव्यवस्था में अन्य निवेश विकल्पों के अभाव को देखते हुए विदेशी वित्तीय निवेशक विशेष रूप से भारत और कुछ अफ्रीकी देशों जैसे उभरते हुए बाजारों के स्टॉक एक्सचेंजों में बेहतर अवसर तलाशते हैं। फेडरल रिजर्व की चेतावनी और अस्थिर भारतीय रुपये तथा शेयर बाजार को देखते हुए विशेष रूप से अमरीकी वित्तीय संस्थानों ने विदेशों (भारत सहित उभरते हुए बाजारों) में निवेश की गई धनराशि निकालनी आरंभ कर दी है। इन विदेशी निवेशकों द्वारा मंदी चाले अर्थव्यवस्थाओं में रुपये की बिक्री तथा डॉलर की खरीद किए जाने से रुपये के मूल्य में और कमी आई है। चूंकि मूल आवक से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की अनेक मुद्राओं को सहारा मिला है और अचानक होने वाली निकासी से इन मुद्राओं के बाहरी मूल्यों में तीव्र गिरावट आई है। रुपये तथा लीरा के मूल्यों में ऐतिहासिक गिरावट से भारत और तुर्की बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यद्यपि, हमारे पास विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं परन्तु, यदि चालू खाते में घाटा बना रहता है और विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय इक्विटी और ऋण बाजार में निवेश नहीं करते हैं तो इसमें तेजी से कमी आएगी। वर्ष 2007-08 से निवल पूंजी आवक के रुझान तालिका 6 में दर्शाए गए हैं। तालिका-7 में वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेश के तिमाही रुझानों को दर्शाया गया है।

तालिका-6: निवल पूंजी आवक (2007-08 से 2011-12)
(जीडीपी का प्रतिशत)

वर्ष	पूंजी आवक
2007-08	8.6
2008-09	6.0
2009-10	3.8
2010-11	3.7
2011-12 (पीआर)	3.6
2012-13 (पी)	5.0

पीआर: आंशिक रूप से संशोधित
पी: प्रारंभिक
स्रोत: वित्त मंत्रालय

*क्यूई, जैसा कि इसका नाम है, फेडरल रिजर्व द्वारा अमरीकी अर्थव्यवस्था के उद्धार हेतु चलाए गए मुद्रा प्रोत्साहन कार्यक्रम को कहा जाता है।

ग्राफ च: 2007-08 से निवल पूंजी आवक (स.घ.उ. का प्रतिशत)

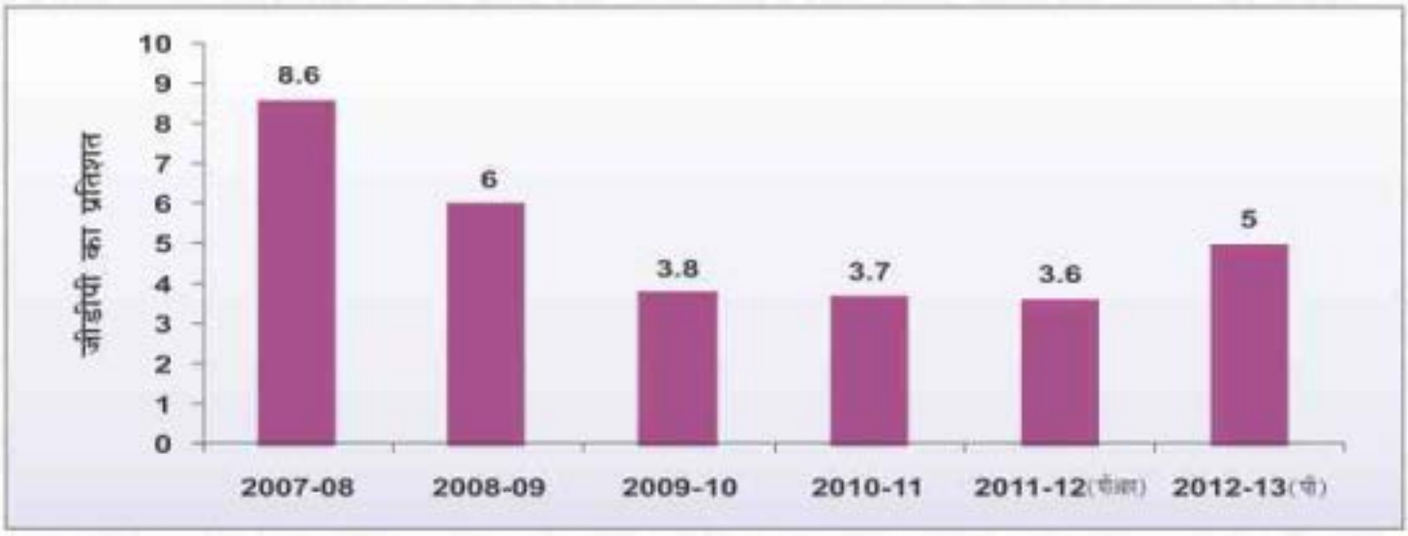

तालिका-7: पृथक-पृथक पूंजी प्रवाह मदें (बिलियन अमरीकी डॉलर)

	2011-12				2012-13			
	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही (प्र.)
निवल प्रत्यक्ष निवेश	9.3	6.5	5.0	1.4	3.8	8.2	2.1	5.7
पोर्टफोलियो निवेश	2.3	–1.4	1.8	13.9	–2.0	7.6	9.8	11.3
अन्य निवेश	12.6	14.2	1.0	1.4	15.4	5.6	20.0	4.2

पी: प्रारंभिक
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

लगातार बनी हुई वैश्विक अस्थिरता

यूरोप में जारी अस्थिरता और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के कारण निवेशक जोखिमपूर्ण निवेश से बचते हैं। इस स्थिति ने भारत में पोर्टफोलियो निवेश को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। इस वैश्विक अस्थिरता ने भारत के भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी खातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है तथा भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम अनुमान (9 जुलाई 2013 के अपने जुलाई 2013 के वर्ल्ड इकॉनामिक आउटलुक में) में यह कहा है कि 2013 में वैश्विक विकास दर 2012 के समान 3 प्रतिशत से कुछ अधिक रहने का अनुमान है। यह अप्रैल, 2013 के वर्ल्ड इकॉनामिक आउटलुक के अनुमान से कम है जो कि मुख्यत: बहुत कमजोर घरेलू मांग और अनेक महत्वपूर्ण उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में धीमी प्रगति तथा यूरो क्षेत्र में दीर्घकालीन मंदी के कारण है। आईएमएफ को आशा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2013 में अप्रैल 2013 के उसके 5.8 प्रतिशत के अनुमान से कम 5.6 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। आईएमएफ ने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को यह चेतावनी जारी की है कि वे उन्हें लंबे समय तक वृद्धि दर में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। आईएमएफ ने यूरो जोन को यह चेतावनी भी जारी की है कि वहां एक दीर्घकालिक मंदी आ सकती है जो कि धीमी गति से उभर रही अर्थव्यवस्थाओं के लिए और अधिक नीतिगत परेशानियां पैदा कर सकती है। इन सभी कारकों का मंदी के दौर से गुजर रहे देशों की मुद्राओं के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सतत मुद्रास्फीति

हाल के दिनों में भारत में मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक रही है। उच्च मुद्रास्फीति से आर्थिक संभावनाओं तथा पूंजी निर्गम की स्थिति बदतर हो जाती है। सामान्य परिस्थितियों में, ब्याज दरों में वृद्धि करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। परन्तु, चूंकि, भारत में पहले से ही ब्याज दरें काफी अधिक हैं अत:, यह विकल्प व्यावहारिक नहीं है क्योंकि, इससे विकास दर में और मंदी आ सकती है।

सुधारों का अभाव

प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) तथा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) जैसे महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार कार्यक्रम वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं। एक भूतलक्षी कर कानून-सामान्य कर अपवंचन नियम (जीएएआर) का व्यापारी वर्ग ने बड़े पैमाने पर विरोध किया है। सरकार ने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की घोषणा की है परन्तु, अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है क्योंकि भारतीय रुपया अब तक के निम्नतम स्तर तक पहुंच चुका है और कुछ वर्ग समुचित नीति के अभाव में सरकार की आलोचना कर रहे हैं।

गिरते हुए रुपये का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव

रुपये के अवमूल्यन से आयात महंगा हो जाता है जोकि भारत के लिए चिंता की बात है क्योंकि यह तेल की अपनी अधिकांश मांग आयात से ही पूरा करता है। तेल के अलावा धातु, स्वर्ण इत्यादि जैसी अन्य आयातित

वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी जिससे समग्र मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। यदि अंतर्राष्ट्रीय तेल और वस्तुओं की कीमतें गिरती भी हैं तब भी भारतीय उपभोक्ताओं को संभवत: लाभ न हो क्योंकि अवमूल्यन से इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। गिरता हुआ रुपया समग्र घरेलू मुद्रास्फीति पर और दबाव बढ़ाएगा। गिरते हुए रुपये का राष्ट्र के विदेशी ऋण आंकड़ों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है।

तेल आयात पर प्रभाव

तेल आयात में देश के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा भाग खर्च हो जाता है। गिरते हुए रुपये से तेल जैसी वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी भी व्यर्थ हो जाएगी। यद्यपि, प्रति बैरल तेल की कीमत में पिछले कुछ महीनों में तेजी से वृद्धि नहीं हुई है फिर भी गिरते हुए रुपये ने आयातकों को कोई राहत नहीं दी है क्योंकि उन्हें उतना ही तेल खरीदने के लिए वास्तव में अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है।

ऋण पर प्रभाव

गिरता हुआ रुपया आयात बिल पर ही प्रभाव नहीं डाल रहा है बल्कि इसने कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए ऋण की लागत को भी अत्यधिक प्रभावित किया है। भारतीय कम्पनियां ईसीबी (विदेशी वाणिज्यिक ऋण) और एफसीसीबी (विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बांड्स) पर बहुत अधिक निर्भर रहती हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र देश के भीतर मुद्रा की कमी से उत्पन्न लागत को बचाने के लिए कुछ माह पूर्व तक ऊंची ब्याज दरों पर विदेशी ऋणों का अधिकांशत: अमरीकी डॉलर में, बहुत अधिक उपयोग करता रहा था परन्तु बाद में रुपये के मूल्य में आई गिरावट ने इन लाभों को आंशिक तौर पर कम कर दिया।

आयातों पर प्रभाव

गिरते हुए रुपये के साथ निर्यातों के मूल्य में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। इसलिए, निर्यातोन्मुखी उद्योगों को विदेशी मुद्रा आय में लाभ होगा। निर्यातकों को संभवत: रुपये के अवमूल्यन से सबसे अधिक लाभ होता है क्योंकि उनकी बिक्री का प्रत्येक डॉलर उनके लिए ज्यादा रुपये लेकर आता है। इस प्रकार यदि बिक्री की उसी मात्रा के साथ वे अपनी कीमतें कम नहीं करते हैं तो उन्हें भारतीय रुपये में अधिक आय होगी। यदि वे बाजार में भागीदारी करना चाहते हैं तो गिरता हुआ रुपया उन्हें डॉलर में अपने उत्पादों की कीमत कम करने के बाद भी रुपये में उतना ही लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और प्रतियोगी बनाता है और डॉलर में सस्ते मूल्यों के कारण अधिक मात्रा में उत्पाद बेचने में सहायक होता है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र: रुपये में तेज गिरावट से सॉफ्टवेयर के निर्यात और विदेशी मुद्रा प्राप्ति में वृद्धि होने की आशा है।

भेषज (फार्मास्युटिकल्स): इस क्षेत्र की कम्पनियां निवल निर्यातकर्ता हैं और गिरते हुए रुपये से बढ़ी हुई ऊंची निर्यात से प्राप्तियों के माध्यम से उन्हें लाभ होता है। विदेशी वाणिज्यिक ऋणों (ईसीबी) पर घाटे और विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) पर समपरिवर्तन की सीमित संभाव्यता इन कम्पनियों के लिए चिंता का विषय हैं परन्तु इनके बहुत बड़े होने की उम्मीद नहीं है।

रत्न और आभूषण: चूंकि यह क्षेत्र निर्यातोन्मुखी है अत: रुपये में गिरावट की प्रवृत्ति से इसे लाभ होने की आशा है।

इन सबसे अलग, भारत में पर्यटन उद्योग और सस्ता हो जाएगा। यह विदेशियों को भारत-यात्रा के लिए प्रोत्साहित करेगा क्योंकि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने के कारण भारत एक आकर्षक पर्यटन स्थल बन गया है।

उच्च मुद्रास्फीति

गिरते हुए रुपये के साथ आयात महंगे हो रहे हैं और इसका सीधा परिणाम यह है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि होती है। ऊंची मुद्रास्फीति से वस्तुएं और महंगी हो रही हैं। चूंकि भारत तेल का प्रमुख आयातक है जिससे अर्थव्यवस्था के लागत ढांचे पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए यदि रुपये का अवमूल्यन होता है तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के परिदृश्य में भारी बदलाव होगा।

ऋण अदायगी

कुछ वर्ष पूर्व विदेशों से सस्ता ऋण लेने का विकल्प सबसे बढ़िया विकल्प था जिसका उपयोग प्रत्येक सक्षम कम्पनी कर रही थी। किन्तु मुद्रा के अवमूल्यन के प्रभाव का अर्थ है कि ऋण लेने वाली कम्पनी को डॉलर में अपने ऋणों की अदायगी के लिए ज्यादा रुपये का भुगतान करना पड़ता था। इसने उनकी वित्तीय गणनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जिससे कुछ कम्पनियां अपने ऋण के भुगतान में चूककर्ता बन गईं।

विदेशी शिक्षा

अधिक से अधिक भारतीय विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं। तथापि, विदेशी शिक्षा सस्ती नहीं मिलती। रुपये के अवमूल्यन के कारण विदेशों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ज्यादा भारतीय रुपया खर्च करना पड़ता है।

रुपये का अवमूल्यन नियंत्रित करने हेतु हाल ही में उठाए गए कदम

स्वर्ण के आयात पर प्रतिबंध

भारत विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा खरीदार है। स्वर्ण के आयात का देश के चालू खाता घाटे की स्थिति और तदनुसार रुपये के मूल्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रुपये का अवमूल्यन रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय के तौर पर सरकार ने बैंकों पर स्वर्ण का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाया है। सोने के आयात को तर्कसंगत बनाने के उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने नामनिर्देशित बैंकों/एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि वे आयातित स्वर्ण की प्रत्येक खेप के पांचवें भाग को विशिष्ट रूप से निर्यात के रूप में उपलब्ध करायें। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण के सिक्कों के बदले ऋण की सुविधा को भी प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही, स्वर्ण का आयात नियंत्रित करने के लिए स्वर्ण पर आयात शुल्क बढ़ाकर 6 से 8 प्रतिशत कर दिया गया है। इन उपायों ने परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि जून 2013 में स्वर्ण के आयात में कमी आई है।

भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा पहल

वर्तमान पद्धति के अनुसार, तेल कम्पनियां बेहतर दरों का पता लगाने में अपनी डॉलर की आवश्यकताओं के लिए अनेक बैंकों से दर-सूची मांगती हैं जिससे डॉलर की सट्टा मांग में वृद्धि होती है। इस सट्टे को नियंत्रित रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों को तेल के आयात हेतु प्रति माह की डॉलर की आवश्यकता सरकारी क्षेत्र के एक ही बैंक से पूरी करने के लिए कहा। इसके अलावा, अब परिसम्पत्ति वित्तपोषण में लगी हुई गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) को डॉलर की आवक बढ़ाने के लिए स्वचालित मांग के अंतर्गत विदेशी वाणिज्यिक ऋणों (ईसीबी) का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी उस एक्सपोजर में कटौती की है जो ब्रोकर और उनके ग्राहक मुद्रा व्युत्पन्नों (वित्तीय साधन) पर लेते हैं और डॉलर-रुपया समझौतों पर उनके लाभ को दुगुना कर देते हैं ताकि विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता कम की जा सके। डेरिवेटिव-ट्रेडिंग को कड़ा करके और साथ ही तेल से जुड़ी डॉलर की मांग का प्रभाव कम करने हेतु संभावित उपायों से गिरते हुए रुपये में राहत मिल सकती है।

कभी-कभी, रुपये का अवमूल्यन नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। परन्तु सरकार को मुद्रा संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत सुधार करने हेतु पहल करने और ईमानदार उपाय करने की आवश्यकता है। आशा है कि रुपया आने वाले दिनों में वापस अपने स्थान पर आ जाएगा और अधिक सुखद स्थिति में पहुंच जाएगा।

इस सूचना बुलेटिन को वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके शोध और सूचना प्रभाग द्वारा संसद सदस्यों के संसदीय कार्य में सहायता हेतु उनके उपयोग के लिए तैयार किया गया। सूचना बुलेटिन तैयार करने से सम्बद्ध अधिकारी: अपर सचिव, श्री पी. के. मिश्रा; निदेशक, श्री सी. एन. सत्यनाथन; अपर निदेशक, डॉ. बी. सी. जोशी और शोध अधिकारी, श्री जयन्त कुमार सामल।